

# सोना-चांदी में आई बड़ी गिरावट

## सोना 1,175 टूटकर 1,56,147 प्रति 10 ग्राम हो गया, चांदी 5,835 टूटी

नई दिल्ली, 12 फरवरी. सर्राफा बाजार में आज सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन आईबीजेए के मुताबिक, चांदी 5,835 गिरकर 2,60,614 प्रति किलो पर आ गई, जबकि 24 कैरेट सोना 1,175 टूटकर 1,56,147 प्रति 10 ग्राम हो गया. हालांकि साल 2026 की शुरुआत से अब तक दोनों धातुओं में तेज बढ़त बनी हुई है, जिससे निवेशकों की नजर बाजार पर टिकी है.

गुरुवार, 12 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली.

आईबीजेए के ताजा आंकड़ों के अनुसार, एक किलो चांदी की 2,66,449 प्रति किलो थी. वहीं 24 कैरेट सोना 1,175 सस्ता होकर 1,56,147 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो एक दिन पहले 1,57,322 था. हालांकि अल्पकालिक गिरावट के बावजूद साल 2026 की शुरुआत से अब तक की तेजी बरकरार है. 31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,33,195 प्रति 10 ग्राम था, यानी 43 दिनों में यह 22,952 महंगा हो चुका है. इसी अवधि में चांदी 30,194 प्रति किलो बढ़ी है. साल 2025 में भी कीमती धातुओं ने जबरदस्त रिटर्न दिया. सोना पूरे वर्ष में करीब 75प्रतिशत चढ़ा, जबकि चांदी में 167प्रतिशत की रिकॉर्ड तेजी रही.



वैश्विक बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी: भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी का असर वैश्विक बाजार में इस समय सोने और चांदी की कीमतों में मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. स्पोर्ट सिल्वर 4.71 डॉलर यानी लगभग 6 प्रतिशत बढ़कर 85.51 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है, जबकि स्पोर्ट गोल्ड 1.06 प्रतिशत बढ़कर 5,078.72 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है.

आईबीजेए के ताजा आंकड़ों के अनुसार, एक किलो चांदी की कीमत 5,835 घटकर 2,60,614 पर पहुंच गई. बुधवार को यह



# रिटेल महंगाई जनवरी में 2.75प्रतिशत पर पहुंची

नई दिल्ली, 12 फरवरी. जनवरी 2026 में भारत में रिटेल महंगाई की दर बढ़कर 2.75प्रतिशत पर पहुंच गई, जो दिसंबर 2025 में 1.33प्रतिशत थी. पिछले महीने के मुकाबले महंगाई में हुई 1.42प्रतिशत की बढ़ोतरी. यह पिछले आठ महीनों में सबसे ज्यादा महंगाई दर है.

सरकार ने गुरुवार, 12 फरवरी को महंगाई के आंकड़े जारी किए, जिसमें यह जानकारी सामने आई. हालांकि, अक्टूबर 2025 में रिटेल महंगाई 0.25न के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई थी. महंगाई दर में इस बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने महंगाई मापने के लिए आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है. इस बदलाव के साथ,

जनवरी 2026 के आंकड़े 2.77प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान था, जैसा कि ब्लूमबर्ग के सर्वे में बताया गया था.

सरकार ने बदलाव किया- नए पैमाने में शामिल हुआ ई-कॉमर्स और एयरफेयर महंगाई की गणना में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन. सरकार ने महंगाई के मापने के लिए पुराने इंडेक्स में कई बदलाव किए हैं. अब खाने-पीने की चीजों का वेटेज घटाकर 36.8प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि पहले यह 50न था. यह बदलाव भारतीयों के दशांता है, क्योंकि अब लोग भोजन पर कम और हाउसिंग तथा अन्य सेवाओं पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं.

**महंगाई मापने का तरीका**

बेस ईयर वह साल होता है जिसकी कीमतों को आधार (बेस) माना जाता है. इसके जरिए यह जाना जाता है कि किसी विशेष समय में चीजों की कीमत कितनी बढ़ी या घटी है. उदाहरण के तौर पर, यदि 2020 को बेस ईयर माना जाए और 2025 में किसी सामान की कीमत 60प्रतिशत बढ़ जाती है, तो इस वृद्धि को महंगाई के रूप में मापा जाता है. अक्टूबर 2025 में रिकॉर्ड निचला स्तर- रिटेल महंगाई 0.25प्रतिशत महंगाई में कमी का मुख्य कारण- खाने-पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट. अक्टूबर 2025 में रिटेल महंगाई 0.25प्रतिशत के रिकॉर्ड निचले स्तर पर थी. इस समय, खाने-पीने की चीजों की कीमतों में कमी के कारण महंगाई में गिरावट आई थी, जो पिछले 14 सालों का सबसे कम आंकड़ा था.

# समाचार विशेष

# संसदीय बोर्ड में होगा बदलाव

## इस बार जो बदलाव होगा वह सिर्फ दिखावे वाला नहीं होगा

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इस बार जो बदलाव होगा वह सिर्फ दिखावे वाला नहीं होगा. ध्यान रहे इससे पहले पिछले 12 साल में पार्टी के संगठन बहुत नहीं बदला है. अमित शाह ने अध्यक्ष बनने के बाद जो टीम बनाई थी उस टीम के लोग हर जगह दिखाई देते हैं.

पार्टी के महामंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्यों के संगठन व सरकार में ऐसे चेहरे दिखेंगे, जो 12 साल पहले आगे लाए गए थे. अमित शाह की टीम को ही मोटे तौर पर जेपी नड्डा ने बनाए रखा और अपने छह साल के कार्यकाल में कुछ नए चेहरे जोड़े. अब कहा जा रहा है कि नितिन नबीन की टीम में बिल्कुल नए चेहरे होंगे. बताया जा रहा है कि संसदीय बोर्ड में फेरबदल होगी. असल में संसदीय बोर्ड में कुछ पदेन सदस्य होते हैं. पार्टी अध्यक्ष के साथ पूर्व अध्यक्ष और दोनों सदनों के नेताओं को इसमें जगह मिलती है. इस नाते नितिन नबीन,

पार्टी के महामंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्यों के संगठन व सरकार में ऐसे चेहरे दिखेंगे, जो 12 साल पहले आगे लाए गए थे. अमित शाह की टीम को ही मोटे तौर पर जेपी नड्डा ने बनाए रखा और अपने छह साल के कार्यकाल में कुछ नए चेहरे जोड़े. अब कहा जा रहा है कि नितिन नबीन की टीम में बिल्कुल नए चेहरे होंगे. बताया जा रहा है कि संसदीय बोर्ड में फेरबदल होगी. असल में संसदीय बोर्ड में कुछ पदेन सदस्य होते हैं. पार्टी अध्यक्ष के साथ पूर्व अध्यक्ष और दोनों सदनों के नेताओं को इसमें जगह मिलती है. इस नाते नितिन नबीन,



नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष पदेन सदस्य हैं.

इनके अलावा जो सदस्य हैं उनमें बीएस येदियुराज, सुधा यादव, इकबाल सिंह लालपुरा, सत्यनारायण जटिया, के लक्ष्मण और सर्वानंद सोनोवाल सदस्य हैं. के लक्ष्मण को ओबीसी चेहरे के तौर पर रखा गया है. माना

आमतौर पर राज्यों के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्रियों को पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया जाता है. हालांकि अब पूर्व मुख्यमंत्रियों में सिर्फ वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष हैं. वे वरिष्ठ नेता हैं पर उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है. कहा जा रहा है कि पुराने और बुजुर्ग नेताओं को दिखावे के लिए उपाध्यक्ष का पद देकर बैठाने की बजाय नए नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि उनसे काम कराया जा सके. उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे बड़े नेताओं में सौदान सिंह, बैजयंत जय पांडा, सरोज पांडे आदि हैं. इनके अलावा डीके अरुणा, अब्दुल्ला कट्टी, तारिक मंसूर, लक्ष्मीकांत बाजपेयी, लता उसेंडी, रेखा वर्मा आदि उपाध्यक्ष हैं. कहा जा रहा है कि प्रकाश जावड़ेकर की उपाध्यक्ष के रूप में वापसी हो सकती है.

जा रहा है कि वे और सोनोवाल पद पर बने रहेंगे. उनके अलावा येदियुराज, लालपुरा, सुधा यादव और जटिया की जगह नए चेहरे आ सकते हैं.

# विशेष सपा ने किया अपना चुनावी अभियान तैयार

# पूर्वांचल नहीं, पश्चिमी उत्तरप्रदेश से शुरुआत

लखनऊ. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है. चुनाव में अभी एक साल बाकी है लेकिन सपा ने पहले ही अपना चुनावी अभियान तैयार कर लिया है. उन्होंने इसे आधिकारिक तौर पर नोएडा से लॉन्च करने का फैसला किया है.

इस कदम को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिले भाजपा के गढ़ रहे हैं. इस क्षेत्र में सपा का प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से कमजोर रहा है. हालांकि, इस बार नोएडा से चुनावी अभियान शुरू करना सपा की र्थािति को



मजबूत करने की एक कोशिश है.

28 मार्च से होगा अभियान का

आगाज- समाजवादी पार्टी ने शनिवार को घोषणा की कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 28 मार्च को अपना चुनावी अभियान शुरू करेंगे. इस बार सपा का अभियान पूर्वांचल से नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होगा. अखिलेश यादव 28 मार्च को नोएडा से 2027 के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे.

रैली रामनवमी के अगले दिन होगी. अपना चुनावी अभियान लगभग 11 महीने पहले शुरू करके अखिलेश यादव ने सपा के लिए सबसे कमजोर क्षेत्र नोएडा को चुना है, क्योंकि नोएडा से वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यह संदेश दे सकते हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो इस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.

# भाजपा के चुनावी वादों का काट

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अमिता बनर्जी की सरकार ने 4.06 लाख करोड़ का अंतरिम बजट विधानसभा में पेश किया है. वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत बजट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.

विश्लेषक इसे बजट से ज्यादा चुनावी घोषणापत्र मान रहे हैं. राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह बजट मुख्य रूप से महिलाओं, युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को लक्षित करता है. विपक्षी दलों का आरोप है कि तुणमूल कांग्रेस ने बजट के माध्यम से अपना चुनावी एजेंडा परिस दिया है. भाजपा इसे वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण से जोड़कर देख रही है. भाजपा शासित राज्यों में लाड़ली बहना जैसी योजनाओं की

सफलता को देखते हुए ममता सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपये की वृद्धि का ऐलान किया है. अब सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये और एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपये मासिक सहायता मिलेगी. भाजपा द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार निशाना साधे जाने के बाद राज्य सरकार ने बांग्ला युवा साथी योजना की घोषणा की है. इसके तहत 21 से 40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने तक या अधिकतम पांच साल के लिए 1500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा. यह योजना 15 अगस्त से लागू होगी. बशर्तें टीएमसी सत्ता में वापस आए, लंबे समय से केंद्रीय दर पर महंगाई भत्ते की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई है.

# नोएडा से होगा 'पीडीए' फार्मूले का ऐलान

सपा सूत्रों के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नोएडा में पीडीए भागीदारी रैली में विधानसभा चुनावों के लिए पीडीएफॉर्मूले की भी घोषणा करेंगे. इस फार्मूले के तहत समाजवादी पार्टी समूचे प्रदेश में 'पीडीए यात्रा' भी निकालने वाली है. कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देंगे जिन्हें पिछले चुनावों में सपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिले की सभी तीन सीटें जीती थीं, और सपा को एक भी सीट नहीं मिली थी. उन्होंने आसपास के जिलों में भी दर्जनों सीटें गंवाई थीं. अब पीडीए नारे के साथ सपा 2027 के विधानसभा चुनावों में पिछड़े और दलित समुदायों को एकजुट करेगी.

मुंबई, 12 फरवरी. स्मार्ट बाजार एक्सचेंज ने स्मार्ट बाजार को रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए भारत के वैल्यू डेस्टिनेशन के तौर पर मजबूत किया. स्मार्ट बाजार , भारत का भरोसेमंद वैल्यू डेस्टिनेशन, ने अपना अब तक का सबसे बड़ा स्मार्ट बाजार एक्सचेंज लॉन्च किया है—यह एक देशव्यापी पहल है जिसे परिवारों को एक ही छत के नीचे ज्यादा बचत करने और स्मार्ट तरीके से खरीदारी करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

स्मार्ट बाजार एक्सचेंज एक आसान, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है- घर के बचे हुए सामान को आज की ज़रूरतों के लिए असली बचत में बदलें. कैंपेन की

टैगलाइन पुराना बेचो महंगा, और नया खरीदो सस्ता. कस्टमर स्मार्ट बाजार स्टोर पर पुराने अखबार, इस्तेमाल किए हुए कपड़े और पुराने बर्तन 100 प्रति केंजी में एक्सचेंज कर सकते हैं, जो बाजार में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज वैल्यू में से एक है. एक्सचेंज वैल्यू स्टोर कूपन के रूप में दी जाती है, जिसे किराने का सामान, घर की ज़रूरी चीज़ें और फ़ैशन



# निवेश में महिलाएं बढ़ीं, म्यूचुअल फंड की ओर रुझान

नई दिल्ली, 12 फरवरी. स्मार्ट निवेश कार्यशाला में आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी के शैलेंद्र दीक्षित ने स्टूक और स्टूक के महत्व को समझाया. उन्होंने बताया कि निवेशक अक्सर रिटर्न पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने लक्ष्यों और रिस्क प्रोफाइल को समझना ज्यादा जरूरी है. कार्यशाला में पिछले साल 30% महिला निवेशकों की भागीदारी ने म्यूचुअल फंड के प्रति जागरूकता को दर्शाया.

# जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी में भारत रहा प्रमुख निर्यातक और उत्पादक तथा सरकारी प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही

नई दिल्ली, 12 फरवरी. भारत ने जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित जैविक उत्पादों के लिए दुनिया के अग्रणी व्यापार मेले, बायोफैच जर्मनी 2026 के उद्घाटन में वर्ष का देश के रूप में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की. इसका उद्घाटन मंगलवार को हुआ जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों सहित देश के विभिन्न राज्यों के बड़ी संख्या में निर्यातक और उत्पादक तथा सरकारी प्रतिनिधियों की उपस्थिति

उद्घाटन समारोह में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने जैविक उत्पादों के क्षेत्र में भारत की अग्रणी स्थिति पर प्रकाश डाला . उन्होंने भारत के जैविक विनियमन, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) में किए गए प्रमुख संशोधनों को रेखांकित किया, जो भारत के जैविक दारो की विश्वसनीयता को और मजबूत करते हैं . उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच अनुपूरकों पर भी जोर दिया, उनकी संयुक्त जनसांख्यिकीय और आर्थिक ताकत को देखते हुए .



इस्तेमाल वे तुरंत अपनी महीने की ज़रूरी चीजों पर कर सकें. यह पहल भारत की सबसे भरोसेमंद वैल्यू डेस्टिनेशन होने के हमारे वादे को और मजबूत करती है.

# पेज 1 का शेष

# गुणवत्ता से किसी ...

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में पीएम गतिशक्ति योजना के माध्यम से लोक निर्माण विभाग नवाचारों को धरातल पर उतार रहा है. लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने क्षमता संवर्धन कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि जब सीध बदलती है तभी व्यवस्था बदलती है, उन्होंने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोक निर्माण विभाग के लिए 293 इंजीनियर्स के पद भरने की स्वीकृति प्रदान की है. इसके लिए विभागीय स्तर पर कार्य जारी है. उन्होंने बताया कि विभाग ने 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले भवनों को ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप निर्मित करने के निर्देशों के पालन में त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियंताओं को इस विषय पर प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया है, सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों के लिए ट्री शिपिंग की एक कार्यशाला भी बहुत जल्द आयोजित की जाएगी.

# देवयानी का भाषण क्यों हो रहा वायरल ?

जम्मू. जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हाल ही में एक ऐसा दुर्लभ और गरिमामय दृश्य देखने को मिला, जिसने दलगत राजनीति की दीवारों को ढहा दिया. अवसर था बजट 2026-27 पर चर्चा का, जहां विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विधायक देवयानी राणा सत्ता पक्ष के तीखे हमलों के बजाय अपने तार्किक और भावुक भाषण के लिए वाहवाही बटोर रही थीं. नागरोटा से विधायक देवयानी ने जब जनहित के मुद्दों पर बोलना शुरू किया तो सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी मेजें थपथपाकर उनका समर्थन करने से खुद को रोक नहीं पाए. देवयानी राणा ने अपने संबोधन में आपदा प्रबंधन और राहत कोष में की गई भारी कटौती को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि पिछले वर्ष का 719 करोड़ रुपये का बजट घटाकर इस बार महज 350.76 करोड़ रुपये कर दिया गया है. उन्होंने याद दिलाया कि जम्मू क्षेत्र, विशेषकर नागरोटा, हाल में बाढ़ और भूस्खलन की त्रासदी झेल चुका है.